उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) इस मामले में की गई प्रारंभिक जांच से यह निष्कर्ष निकला है कि यह बात सन्देहास्पद है कि क्या डी जी एस एंड डी को दिये गये कंबलों का निर्माण वास्तव में के वी आई सी द्वारा किया गया था। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद सरकार ने के वी आई सी को अपने उन कर्मचारियों के विरुद्ध यथासंभव कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निदेश दिये हैं जिन्होंने देहरादून स्थित तीन संस्थाओं में कुछ अवांछनीय तत्वों को स्पष्टतया गुप्त सहयोग दिया था जिन्होंने बैरक कंबलों की आपूर्ति के लिये थोक आदेश प्राप्त किये थे।

वैयक्तिक उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये और जांच करने हेतु के०वी०आई० सी० द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

Industrialization of backward areas

1443. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have made any assessment regarding response to its policy for establishing industries in backward areas;

(b) if so, the details thereof;

(c) the number of no industry' districts which are still to be provided with industries; and

(d) the steps taken to accelerate growth process in the no industry' districts?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) An Inter-Ministerial Committee was set up by the Central Government in 1985 to review and revise the Scheme of industrialisation of backward areas based on the concept of growth centres.

(c) and (d) Industrialisation of any district or area is essentially the responsibility of the State Government concerned and the Central Government supplement such efforts wherever possible. Since 1983 to June, 1993, 710 letters of intent and 192 industrial licences have been issued to the No Industry District in the country. The Central Government are also operating a Growth Centre Scheme for provision of infrastructural facilities to the less industrialised regions. Under this Scheme, some of the centres are located in the No industry Districts.

उत्तर प्रदेश में विकास-केन्द्र

1444. **श्री ईश दत्त यादव**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों के लिये आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिये सरकारी विकास केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर विकास केन्द्र स्थापित किए गए हैं और गत पांच वर्षों के दौरान कितनी सहायता राशि प्रदान की गई है ;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इन विकास केन्द्रों ने कितने कार्य किए हैं ; और

(घ) विकास केन्द्रों की नई योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में किस स्थान को चुना गया ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) देश में उद्योगों का क्षेत्रीय छितराव करने के उद्देश्य से सरकार एक विकास केन्द्र योजना चला रही है जिसे 8वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अधीन सारे देश में प्रति विकास केन्द्र 25–30 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जायेगा और इन्हें बिजली, पानी दूरसंचार इत्यादि